सामान्य जानकारी

दिल्ली में प्रशासन की वर्तमान प्रणाली 1803 में देखी जा सकती है, जब दिल्ली ब्रिटिश सुरक्षा में आ गई और अंत में ब्रिटिश पंजाब का हिस्सा बन गई। दिल्ली जिले में एक डिप्टी कमिश्नर थे जो मुख्य जिला अधिकारी थे, जिसमें राजस्व और पंजीकरण शक्तियां थीं। वह जिला बोर्ड और नगर पालिका के अध्यक्ष होने के नाते शहरी प्रशासन के प्रमुख भी थे।

आजादी तक, डिप्टी कमिश्नर रिपोर्टिंग के साथ, दिल्ली के प्रशासनिक और कार्यकारी प्रमुख के रूप में एक मुख्य आयुक्त थे। उनके पास तीन सहायक आयुक्त थे, जैसे राजस्व और आपराधिक अपील, नगरपालिका और मामूली आपराधिक मामलों और नगर पालिका के प्रशासन जैसे जिम्मेदारियों को साझा करना।

आजादी के बाद, जिला प्रशासन की प्रकृति ने नए बनाए गए विभागों को शक्तियों के विभाजन के साथ कुछ बदलाव किए। उदाहरण के लिए, नगर पालिका एमसीडी में विकसित हुई, जिसमें डीसी की 1 9 58 के बाद कोई भूमिका नहीं थी। विकास कार्यों को विकास आयुक्त में स्थानांतरित कर दिया गया, उद्योग निदेशालय उद्योग में काम करते थे और परिवहन विभाग परिवहन के काम में काम करते थे।

हालांकि, डीसी, दिल्ली राजस्व और आपराधिक न्यायिक कार्य के अलावा कानून और व्यवस्था, उत्पाद शुल्क, हथियार जारी करने और विस्फोटक लाइसेंस, और नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए जिला प्रशासन का प्रमुख बने रहे। सत्तर के दशक के मध्य में, डीसी कार्यालय का आयोजन निम्नानुसार किया गया था - ये चार प्रशासनिक जिलों थे - नई, मध्य, उत्तर और दक्षिण, तीन एडीएम की अध्यक्षता में थे, जिनमें से कई अन्य शक्तियां और कार्य, जैसे खजाने, उत्पाद, मनोरंजन आदि, विभाजित थे। राजस्व और भूमि अधिग्रहण कार्य की निगरानी क्रमशः एडीएम (राजस्व) और एडीएम (एलए) द्वारा की गई थी। 12 उप-प्रभाग थे, जिनमें से प्रत्येक एसडीएम की अध्यक्षता में था, जिसे बाद में सात कर दिया गया था।

दो बड़े बदलावों ने डीसी कार्यालय की भूमिका को बहुत कम कर दिया। पहला 1 9 6 9 में कार्यकारी और न्यायपालिका को अलग करना था, जिसके बाद सत्र न्यायालयों द्वारा गंभीर अपराधों का सामना किया गया था और आईपीसी अपराधों सहित अन्य अपराधों को न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा निपटाया गया था। कार्यकारी मजिस्ट्रेट को कार्यकारी और प्रशासनिक मामलों जैसे लाइसेंसिंग, अभियोजन पक्ष की मंजूरी, और सीआरपीसी के निवारक वर्गों की देखभाल करना था। जैसे धारा 107,10 9,110,133,144 और 145।

1 9 78 में, दिल्ली पुलिस अधिनियम की घोषणा की गई, जिसके द्वारा सीआरपीसी के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट की लगभग सभी शक्तियां दिल्ली पुलिस आयुक्त के अधीन आई। धारा 107 और धारा 144 सीआरपी, जो कि कानून और व्यवस्था जैसे बहुत महत्वपूर्ण हैं, पुलिस आयुक्त में निहित थे। तब से सीधे पुलिस द्वारा निपटाया गया है। इसके अलावा, लाइसेंसिंग और मनोरंजन की शक्तियां, जो पहले डीसी में निहित थीं, तब से सीधे दिल्ली पुलिस आयुक्त के अधीन आई।

1 99 6 में यह स्थिति थी जब 27 एसडीएम कार्यालयों और 9 डीसी कार्यालयों की स्थापना करके डीसी कार्यालय को विकेंद्रीकृत करने का अभ्यास शुरू किया गया था। जबकि 1 99 6 के मध्य में एसडीएम लगाए गए थे, डीसी 1.1.9 7 से काम करना शुरू कर दिया था। सितंबर 2012 में, दिल्ली 11 जिलों और 33 उपविभागों में विचलित हो गया था।

परिचय

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम जिला दिल्ली का दक्षिण पश्चिम भाग दिल्ली में स्थित है। यह अक्षांश 28 40 'और 28 2 9' और 76 50 'और 77 14' के बीच रेखांश के बीच स्थित है।

जिले में 2,292,958 की आबादी से लगभग 420 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। 1,246,046 पुरुष और 1,046,912 महिलाएं हैं। जिले के 77 गांव हैं।

जिला तीन प्रशासनिक उपखंडों में विभाजित है – दिल्ली छावनी उप-प्रभाग, वसंत विहार उप डिवीजन और नजफगढ़ उप-मंडल। तीन प्रशासनिक तहसील – दिल्ली छावनी, वसंत विहार और नजफगढ़ हैं।

दक्षिण पश्चिम जिला रणनीतिक महत्व का है क्योंकि इसमें दिल्ली में हवाई अड्डे दोनों हैं – इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ-साथ घरेलू पलाम हवाई अड्डा। जिला में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दिल्ली छावनी है जिसमें बड़ी संख्या में रक्षा कर्मियों के अलावा कई रक्षा प्रतिष्ठान, तोपखाने, हथियार आदि हैं।

जिले में आरके पूरम में बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारी भी हैं। दक्षिण-पश्चिम जिले में द्वारका में एशिया में सबसे बड़ी कॉलोनी होने का गौरव है। इसके अलावा आरके पूरम, एशिया में सबसे बड़ी सरकारी उपनिवेश भी जिले के अंतर्गत आता है। इस जिले के पलाम गांव 365 गांवों के पंचायत का प्रमुख है।

स्थान और भूगोल

दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले के उत्तर में झज्जर, दक्षिण में गुड़गांव और पूर्व में दिल्ली के दक्षिण जिले से घिरा हुआ है। यह गुड़गांव, बहादुरगढ़ और झज्जर और पश्चिम, मध्य, नई दिल्ली और दिल्ली के एनसीटी के दक्षिण जिले में हरियाणा की सीमा से घिरा हुआ है।

जिला प्रशासन

जिला प्रशासन सरकार और आम आदमी के बीच एक पुल है। इस प्रणाली में भारत में एक लंबी परंपरा है और स्वतंत्रता से पहले भी अपनाया गया है। दक्षिण-पश्चिम जिले का नेतृत्व उप आयुक्त द्वारा किया जाता है जिसके बाद अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) दूसरे-1 एन-कमांड के रूप में होता है। एडीएम जिले के भूमि अधिग्रहण

कलेक्टर के रूप में कार्य करता है और भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण करने, सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए जमीन के लिए मुआवजे का आकलन करने के कार्यों को पूरा करता है।

जिला को 3 उपविभागों में बांटा गया है और उप मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) प्रत्येक उपविभाग का प्रमुख है। प्रत्येक उपखंड में अपने विभिन्न कार्यों के लिए राजस्व और लिपिक कर्मचारी होते हैं। राजस्व कार्यों के लिए प्रत्येक उपखंड में उस क्रम में तहसीलदार, नाइब-तहसीलदार, कनुनगो और पटवार हैं। अन्य कार्यों के लिए, क्लर्किकल स्टाफ हैं।

तीन उप-प्रभाग हैं: –

1. कापसहेड़ा
2. नजफगढ़
3. द्वारका

दक्षिण पश्चिम जिले में मुख्य रूप से ग्रामीण, नजफगढ़ उप डिवीजनों और द्वारका सब डिवीजन शहरी और ग्रामीण दोनों के मिश्रण के रूप में कपाशेरा सब डिवीजन के साथ एक विविध चरित्र है।

निर्वाचन कर्तव्यों का प्रदर्शन करने के लिए उप मुख्य आयुक्त (दक्षिण-पश्चिम) को संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (दक्षिण-पश्चिम) के रूप में भी नामित किया गया है। इस काम में, दस्तावेजों के पंजीकरण के कार्य के संबंध में सभी एसडीएम और एसडीएम (चुनाव) द्वारा उनकी सहायता की जाती है, बीडीओ के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत सीधे उप-रजिस्ट्रार (दक्षिण-पश्चिम) का कार्यालय होता है। (दक्षिण-पश्चिम) भी डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय का हिस्सा है। ब्लॉक विकास अधिकारी की अध्यक्षता में, यह कार्यालय गांव में कृषि, बागवानी और विकास गतिविधियों के प्रचार के लिए गॉन सभा भूमि और हिरासत के लिए उत्तरदायी है। जिले में कम्प्यूटरीकरण की सुविधा प्रदान करते समय जिले में एनआईसी का एक केंद्र भी है और जिले को इंटरनेट के माध्यम से दुनिया से जोड़ता है।

डिप्टी कमिश्नर (दक्षिण-पश्चिम) का कार्यालय जनता को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है जैसे: –

भूमि के स्वामित्व से संबंधित सेवाएं
प्रमाण पत्र जारी करना
विवाह का पंजीकरण
दस्तावेजों का पंजीकरण
राहत और पुनर्वास
स्व रोजगार के लिए ऋण
दस्तावेज़ों की मुद्रांकन
खाद्य अपवर्तन अधिनियम की रोकथाम के तहत एलएचए के कार्य
सीआर पीसी के तहत मजिस्ट्रेट के कार्य
भूमि अधिग्रहण

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत नियामक कार्य
विभिन्न कार्यों, नियमों और नियंत्रण आदेशों के तहत विविध कार्य

उपखंड और ब्लॉक

दक्षिण पश्चिम जिले में तीन उप विभाजन हैं

1. **कापसहेड़ा**
2. **नजफगढ़**
3. **द्वारका**

जिले पुलिस जिलों से मेल खाते हैं। इस जिले का नेतृत्व एक डिप्टी कमिश्नर होता है, जिसके अधीन उसके अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उप मंडल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और उप-रजिस्ट्रार हैं। जिला प्रशासन में मजिस्ट्रेट मामलों, राजस्व अदालतों, विभिन्न सांविधिक दस्तावेजों के मुद्दे, संपत्ति का पंजीकरण, चुनाव आचरण, राहत और पुनर्वास, भूमि अधिग्रहण और कई अन्य क्षेत्रों सहित विभिन्न प्रकार के कार्यों को शामिल किया गया है, जो संख्यात्मक होने के लिए बहुत अधिक हैं। दिल्ली में जिला प्रशासन सभी प्रकार की सरकारी नीतियों के लिए डी-फैक्टो प्रवर्तन विभाग है और सरकार के कई अन्य कार्यकर्ताओं पर पर्यवेक्षी शक्तियों का उपयोग करता है।
राजस्व पदानुक्रम के शीर्ष पर विभागीय आयुक्त है जो दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट और पंजीकरण महानिरीक्षक भी हैं। उन्हें विभिन्न राजस्व अधिनियमों के तहत सचिव (राजस्व) और कलेक्टर के रूप में भी नामित किया गया है।

कार्य

राजस्व कार्य

राजस्व कार्यों में भूमि अभिलेखों का रखरखाव, राजस्व मामलों का आचरण, सीमांकन और उत्परिवर्तन, निपटान संचालन और सार्वजनिक भूमि के संरक्षक के रूप में कार्य करना शामिल है। दिल्ली में परिचालित विभिन्न राजस्व कानूनों के अनुसार उप आयुक्त और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट संग्राहक और अतिरिक्त संग्राहक हैं। उप मंडल मजिस्ट्रेट सहायक संग्राहक और राजस्व सहायक के रूप में नामित हैं और मुख्य रूप से दिन-प्रतिदिन राजस्व कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। गिर्दवार, कनंगों और पटवारी के अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों की निगरानी तहसीलदार द्वारा की जाती है जो क्षेत्र स्तर की राजस्व गतिविधियों और उत्परिवर्तनों में शामिल होते हैं।

प्रमाण पत्र जारी करना

उप मंडल; मजिस्ट्रेट को एससी / एसटी और ओबीसी, डोमिनिक, नेशनलिटी इत्यादि सहित विभिन्न प्रकार के सांविधिक प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार दिया जाता है।
संपत्ति दस्तावेजों, बिक्री कार्यों, वकील की शक्ति, शेयर प्रमाण पत्र और कानून के अनुसार अनिवार्य रूप से पंजीकृत होने वाले अन्य सभी दस्तावेजों का पंजीकरण सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में किया जाता है जो संख्या में नौ हैं। उप आयुक्त अपने संबंधित जिलों के लिए रजिस्ट्रार हैं और सब रजिस्ट्रारों पर पर्यवेक्षी नियंत्रण का प्रयोग करते हैं।

चुनाव कार्य

संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उप आयुक्त जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और उप मंडल मजिस्ट्रेट मतदाता सूची के संबंध में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों के लिए रिटर्निंग अधिकारी हैं। जिला अधिकारी मुख्य रूप से लोकसभा और विधानसभा चुनावों के संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी कार्ड) और मतदाता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिला प्रशासन मतदाताओं की सूची के रखरखाव और संशोधन के लिए भी जिम्मेदार है।

अदालती कार्य

उप आयुक्त, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और उप मंडल मजिस्ट्रेट कार्यकारी मजिस्ट्रेट्स की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इस भूमिका में वे आपराधिक प्रक्रिया संहिता के निवारक अनुभागों के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं। वे शादी के सात साल के भीतर महिलाओं की अप्राकृतिक मौतों के मामलों में पूछताछ भी करते हैं और यदि आवश्यक हो तो मामले के पंजीकरण के लिए पुलिस को निर्देश जारी करते हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और उप मंडल मजिस्ट्रेट को पुलिस लॉक अप, जेल, महिला गृह आदि में मौत सहित संरक्षक मौतों में पूछताछ करने का अधिकार दिया जाता है। इस विभाग के अधिकारियों को भी सरकार की आंखों और कानों के रूप में कार्य करने की उम्मीद है और सभी में पूछताछ आयोजित की जाती है। प्रमुख आग की घटनाओं, दंगों और प्राकृतिक आपदाओं आदि सहित प्रमुख दुर्घटनाएं

विवाह का पंजीकरण

उप आयुक्त, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और उप मंडल मजिस्ट्रेट को हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह के रजिस्ट्रार के रूप में शक्तियों से सम्मानित किया जाता है। यह शक्ति आमतौर पर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग की जाती है जो पंजीकरण और विवाह के गंभीरकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं।

राहत और पुनर्वास

प्राकृतिक या मानव-एमडीई चाहे किसी भी आपदा में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए इस विभाग को प्राथमिक जिम्मेदारी दी जाती है। उप आयुक्तों के कार्यालय बाढ़, आग, फसल विफलताओं, सूखे और अन्य आपदाओं के दौरान राहत अभियान चलाते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से प्राकृतिक और रासायनिक आपदाओं और आपदा तैयार करने पर जागरूकता निर्माण कार्यक्रम के लिए आपदा प्रबंधन योजना के समन्वय और कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है। यह विभाग प्रवासी शिविरों के प्रबंधन और जम्मू-कश्मीर प्रवासियों, पंजाब प्रवासियों और 1 9 84 के दंगों पीड़ितों को राहत और पेंशन के वितरण में भी शामिल है।

गाँव

जिला दक्षिण-पश्चिम में गांवों की सूची

उप विभाजन – द्वारका

1. तोगन पुर
2. पालम
3. बिन्दापुर
4. लुहार हेड़ी
5. मिरजापुर
6. नसीरपुर
7. डाबरी
8. धूल सिरस
9. पोछन पुर
10. अन्बर हेड़ी
11. नंगली सकरावती
12. ककरोला
13. बुधेला
14. हस्ताल
15. नंगली जालिब
16. रजापुर खुर्द

17. पोसंगीपुर
18. नवादा माजरा हस्ताल
19. मटियाला
20. असालतपुर खादर

उप विभाजन – नजफगढ़

1. रोशन पुरा
2. डिचाऊँ कलाँ
3. झड़ोदा कलाँ
4. सुरख पुर
5. मित्राऊँ
6. खड़खड़ी नाहर
7. खैरा
8. सुरहेड़ा
9. कैर
10. खेड़ा डाबर
11. उजवा
12. शेर पुर डेयरी
13. जाफ्फरपुर कलाँ
14. मलिकपुर जेर
15. झुलझुली
16. सारंगपुर
17. मुन्ढेला कलाँ
18. मुन्ढेला खुर्द
19. समसपुर खालसा
20. ईसापुर
21. काजीपुर
22. बाक्करगढ़
23. ढांसा
24. गालिब पुर
25. नजफगढ़
26. हैबत पुर
27. मसूदाबाद

उप विभाजन – कापसहेड़ा

1. भरथल
2. बामनौली
3. घुमनहेड़ा
4. दरयापुर खुर्द
5. रावता
6. देवराला
7. पिन्डवाला कलाँ
8. पिन्डवाला खुर्द
9. खड़खड़ी जटमल
10. खड़खड़ी रौंद
11. झटीकरा
12. राघोपुर
13. नानक हेड़ी
14. बड़ू सराय
15. शिकार पुर
16. असालतपुर खावद
17. जैन पुर
18. हसनपुर
19. दौलतपुर
20. रेवला खानपुर
21. पपरावट
22. गोयला खुर्द
23. ताजपुर खुर्द
24. कुतबापुर
25. छावला
26. कांगनहेड़ी
27. सालहपुर
28. कापसहेड़ा
29. बिजवासन
30. दीनदारपुर

पुलिस स्टेशन

जिला दक्षिण-पश्चिम के पुलिस स्टेशनों की सूची

1. पुलिस उपायुक्त (एसडब्ल्यू), वसंत विहार।
2. पुलिस उपायुक्त (द्वारका), सेक्टर -223
3. सहायक पुलिस आयुक्त, वसंत विहार
4. सहायक पुलिस आयुक्त, वसंत कुंज
5. सहायक पुलिस आयुक्त, दिल्ली कैंट
6. पुलिस स्टेशन सेक्टर 23 द्वारका
7. पुलिस स्टेशन द्वारका (उत्तर)
8. पुलिस स्टेशन कपशेरा
9. पुलिस स्टेशन द्वारका दक्षिण
10. सहायक पुलिस आयुक्त, दबरी
11. पुलिस स्टेशन, दबरी
12. पुलिस स्टेशन, बिंदपुर
13. पुलिस स्टेशन, पलाम गांव
14. पुलिस स्टेशन, सागर पूर
15. सहायक पुलिस आयुक्त, नजफगढ़
16. पुलिस स्टेशन, नजफगढ़
17. पुलिस स्टेशन, जाफरपुर कलान
18. पुलिस स्टेशन, छावाला
19. पुलिस स्टेशन बाबा हरि दास नगर
20. पुलिस स्टेशन, विकासपुरी
21. पुलिस स्टेशन, उत्तमनगर
22. पुलिस स्टेशन, जनकपुरी
23. पुलिस स्टेशन, तिलकनगर